

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2016

विषय:-उत्तर प्रदेश में एसिड (तेजाब) की खुलेआम बिक्री को नियंत्रित करने के लिए निर्गत
उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1160/छः-पु0-9-16-31(90)/2010 दिनांक 10 मई, 2016 एवं संख्या- 1160 (1)/छः-पु0-9-16-31(90)/2010 दिनांक 11 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा किमिनल रिट याचिका संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य आदेशों के साथ-साथ एसिड (तेजाब) के कय-विक्रय तथा भण्डारण को विनियमित करने तथा उनका कठोरता से प्रवर्तन करने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या एस0सी0- 06(1)/छः-पु0-9-13-31(90)/2010 दिनांक 16.8.2013 एवं तत्कम में दिनांक 14.07.2014 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 में विहित प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की मासिक सूचना गृह विभाग के फैक्स-0522-2238409/2238407 अथवा ईमेल- shome@nic.in पर प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-18294/2016 मुहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 03 अन्य में दिनांक 11.05.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गये हैं:-

In Laxmi vs. Union of India: Writ Petition (Criminal) No.-129 of 2006, the following directions were issued by the Supreme Court in regard to regulating the sale of acid and other corrosive substances:

“In the States/Union Territories, where rules to regulate sale of acid and other corrosive substances are not operational, until such rules are framed and made operational, the Chief Secretaries of the concerned States/ Administrators of the Union Territories shall ensure the compliance of the following directions with immediate effect.

- (i) Over the counter, sale of acid is completely prohibited unless the seller maintains a log/register recording the sale of acid which will contain the details of the person (s) to whom acid (s) is/are sold and the quantity sold. The log/register shall contain the address of the person to whom it is sold.
- (ii) All sellers shall sell acid only after the buyer has shown : (a) a photo ID issued by the Government which 2 also has the address of the person; (b) specifies the reason/purpose for procuring acid.
- (iii) All stocks of acid must the declared by the seller with the concerned Sub-Divisional Magistrate (SDM) within 15 days.
- (iv) No acid shall be sold to any person who is below 18 years of age.

(v) In case of undeclared stock of acid, it will be open to the concerned SDM to confiscate the stock and suitably impose fine on such seller up to Rs.50,000/-

(vi) The concerned SDM may impose fine up to Rs.50,000/- on any person who commits breach of any of the above directions.”

The State of UP has formulated rules in 2014 which have been gazetted on 14 July 2014. Recently, following the previous order of this Court dated 4 May 2016, the Secretary to the State Government has issued a government order dated 10 May 2016 to all the Collectors as well as Senior Superintendents of Police (or as the case may be the Superintendents of Police) for strict enforcement of the provisions contained in the rules. On this aspect, the Court should have the benefit of a full and complete affidavit setting out the enforcement action which has been taken and the steps which have been adopted by the Collectors to ensure compliance with the rules.

Insofar as the enhancement of compensation to the victims 3 whose names have been spelt out in prayer (i), we deem it appropriate and proper to await the evaluation by the Medical Board as has been directed in the previous order dated 4 May 2016 and the report to be submitted thereon by the District Collector. The District Collector, we clarify, would be at liberty to take an independent decision on its own which will be subject to further orders which may be passed in these proceedings.

The petition shall now be listed under the same caption on 12 July 2016 to facilitate compliance.

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में शासन से प्रदत्त निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 में विहित प्रावधानों के अनुक्रम में जनपद स्तर पर तेजाब की बिक्री की रोकथाम इत्यादि के संबंध में की गयी कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति से दिनांक 20.6.2016 तक शासन को गृह विभाग के फ़ैक्स-0522-2238409/2238407 अथवा ईमेल-shome@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- प्रकरण में आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

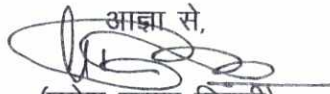
भविदीय, 9

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या: एवं दिनांक: उपरोक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) महानिदेशक अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
- (4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।